

Waqf Act 1995 vs 2025: A Detailed Comparison



The "new Waqf bill" you're referring to is likely the Waqf (Amendment) Bill, 2025, which was passed by the Indian Parliament in April 2025, amending the Waqf Act, 1995. Since I don't have a "previous Bwaqf bill" to compare it with (assuming "bwaqf" is a typo), I'll compare the 2025 amendments with the original Waqf Act, 1995, which governed Waqf properties in India prior to these changes. Below is an overview of the new bill and a comparison with the 1995 Act based on available information up to April 3, 2025.

जिस " **नए वक्फ विधेयक** " का ज़िक्र कर रहे हैं, वह संभवतः वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 है, जिसे भारतीय संसद ने अप्रैल 2025 में पारित किया था और वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया था। चूँिक मेरे पास तुलना करने के लिए कोई "पिछला वक्फ विधेयक" नहीं है (यह मानते हुए कि " वक्फ " एक टाइपो है), मैं 2025 के संशोधनों की तुलना मूल वक्फ अधिनियम, 1995 से करूँगा, जो इन बदलावों से पहले भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता था। नीचे 3 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर नए विधेयक का अवलोकन और 1995 के अधिनियम से तुलना दी गई है।

Overview of the Waqf (Amendment) Bill, 2025

The Waqf (Amendment) Bill, 2025, also referred to as the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development (UMEED) Act, introduces significant reforms to the administration, transparency, and inclusivity of Waqf properties in India. Waqf refers to properties dedicated by Muslims for religious, charitable, or pious purposes under Islamic law, managed by Waqf Boards and overseen by the Central Waqf Council. The 2025 bill addresses long-standing issues like mismanagement, lack of transparency, and disputes over property claims, while sparking debate over government oversight and religious autonomy.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का अवलोकन

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम भी कहा जाता है, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, पारदर्शिता और समावेशिता में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है। वक्फ, इस्लामी कानून के तहत मुसलमानों द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है, जिनका प्रबंधन वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है और केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। 2025 का यह विधेयक कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और संपत्ति के दावों पर विवाद जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करता है, साथ ही सरकारी निगरानी और धार्मिक स्वायत्तता पर बहस को भी जन्म देता है।



Page-1





Key Features of the 2025 Bill / 2025 विधेयक की मुख्य विशेषताएं

Renaming and Intent:

- Renames the Waqf Act, 1995, to the "Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 1995" (UMEED), signaling a focus on modernization and efficiency.
- Aims to enhance transparency, accountability, and inclusivity in Waqf governance.

नाम बदलना और डरादा:

- वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" (यूएमईईडी) कर दिया गया है, जो आधुनिकीकरण और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है ।
- इसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढाना है।

2. **Composition of Wagf Boards and Central Wagf Council:**

- Mandates inclusion of two non-Muslim members in both the Central Waqf Council and State Waqf Boards.
- Requires two Muslim women on these bodies, promoting gender equality.
- Removes the requirement that the Chief Executive Officer (CEO) of a Wagf Board must be Muslim, opening the role to non-Muslims.

वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना:

- केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है।
- इन निकायों में दो मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे लैंगिक समानता को बढावा मिलेगा।
- वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के मुस्लिम होने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है, तथा गैर-मुस्लिमों के लिए भी यह भूमिका खोल दी गई है।

Survey and Property Disputes: 3.

- Replaces the Survey Commissioner with the District Collector (or a deputy-level officer) to survey Waqf properties, aligning records with state revenue laws.
- Government properties identified as Wagf will cease to be recognized as such, with the Collector determining ownership and updating revenue records.
- Removes the "Waqf by user" provision (where long-term use could designate a property as Waqf), though existing Waqf-by-user properties registered before the bill remain valid unless disputed by the government.

सर्वेक्षण और संपत्ति विवाद:

- वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर (या उप-स्तर के अधिकारी) को नियुक्त किया जाएगा, तथा अभिलेखों को राज्य के राजस्व कानूनों के अनुरूप बनाया जाएगा।
- वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियों को उस रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, तथा कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा।
- "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" प्रावधान को हटा दिया गया है (जहां दीर्घकालिक उपयोग से किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में नामित किया जा सकता था), हालांकि बिल से पहले पंजीकृत मौजूदा वक्फ-उपयोगकर्ता संपत्तियां तब तक वैध रहेंगी जब तक कि सरकार द्वारा विवाद न किया जाए।

4. **Registration and Transparency:**

- Mandates all Wagf properties be registered on a centralized portal within six months of the law's enactment, with exceptions allowed by Waqf Tribunals.
- Introduces audits by the Comptroller and Auditor General (CAG) or a designated officer for Wagf institutions earning over ₹1 lakh annually.

पंजीकरण और पारदर्शिता:

- कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है, वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा अनमत अपवादों के साथ।
- 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाली वक्फ संस्थाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) या किसी नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट की व्यवस्था लागू की गई है।

5. **Wagf Creation Rules:**

Only a person practicing Islam for at least five years can dedicate property as Waqf, and they must own the property.

Page-2







Link Life with Law

• Ensures inheritance rights (especially for women) are not denied in family Waqf (waqf-alal-aulad).

वक्फ निर्माण नियम:

- केवल कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकता है, और संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक वक्फ (वक्फ -अल औलाद) में उत्तराधिकार के अधिकार (विशेषकर महिलाओं के लिए) से इनकार न किया जाए।

6. Tribunal and Appeals:

- Reforms Waqf Tribunals to include a District Judge, a Joint Secretary-level officer, and removes the mandatory Muslim law expert.
- Allows appeals against Tribunal decisions to the High Court within 90 days, applying the Limitation Act, 1963, to Wagf claims.

न्यायाधिकरण और अपील:

- वक्फ न्यायाधिकरणों में सुधार करके इसमें एक जिला न्यायाधीश, एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को शामिल किया गया तथा अनिवार्य मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की नियुक्ति को हटा दिया गया।
- वक्फ दावों पर सीमा अधिनियम, 1963 को लागू करते हुए, 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है।

7. Financial Reforms:

• Reduces mandatory contributions from Waqf institutions to Waqf Boards from 7% to 5%, freeing up funds for charitable purposes.

वित्तीय सुधार:

• वक्फ संस्थाओं द्वारा वक्फ बोर्डों को दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे धर्मार्थ कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

8. Sectarian Inclusivity:

• Provides for separate Waqf Boards for Bohra and Aghakhani communities, alongside existing provisions for Shia and Sunni Boards where applicable.

सांप्रदायिक समावेशिता:

• जहां लागू हो, शिया और सुन्नी बोर्डों के लिए मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ बोहरा और अगाखानी समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करता है।

Comparison with the Waqf Act, 1995

The Waqf Act, 1995, was a comprehensive law enacted to regulate Waqf properties, replacing earlier legislation like the Waqf Act, 1954, and the Mussalman Wakf Act, 1923. The 2013 amendments to the 1995 Act had already expanded Waqf Board powers, but the 2025 bill shifts the framework significantly. Here's a detailed comparison:

वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून था, जिसने वक्फ अधिनियम, 1954 और मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 जैसे पूर्ववर्ती कानूनों का स्थान लिया। 1995 के अधिनियम में 2013 के संशोधनों ने पहले ही वक्फ बोर्ड की शक्तियों का विस्तार कर दिया था, लेकिन 2025 का विधेयक इस ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। यहाँ एक विस्तृत तुलना दी गई है:

Aspect	Waqf Act, 1995 (with 2013 Amendments)	Waqf (Amendment) Bill, 2025
Name	Waqf Act, 1995	Unified Waqf Management,
		Empowerment, Efficiency, and
		Development (UMEED) Act, 1995
All members (except ex-officio) mus		Includes two non-Muslim members;
Waqf Board Composition be Muslim; at least two women two Muslim wor		two Muslim women mandatory; state
	required. Elections from Muslim MPs,	nominates all members, no elections.
	MLAs, Bar Council members.	





©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com

CEO Requirement	Must be a Muslim officer (Deputy	No religious requirement for CEO.	
-	Secretary rank or equivalent).		
Survey Authority	Survey Commissioner appointed by	District Collector or deputy-level	
	the state.	officer.	
Waqf by User	Waqf by User Recognized properties used long-term		
	for religious purposes as Waqf, even	Waqf-by-user properties remain unless	
	without documentation.	disputed.	
Property Disputes	Waqf Board could determine Waqf	Collector investigates; Tribunal	
	status (Section 40); Tribunal decisions	decisions appealable to High Court	
	final unless High Court intervened in	within 90 days.	
	rare cases.		
Transparency	No mandatory central portal; limited	Centralized portal for registration; CAG	
	audit provisions.	audits for high-income Waqfs.	
Waqf Creation	Any Muslim could create Waqf; no	Must practice Islam for 5+ years;	
	explicit practice duration.	inheritance rights protected.	
Tribunal Structure	Three members: Judge, Additional	Three members: District Judge, Joint	
	District Magistrate, Muslim law expert.	Secretary, no Muslim law expert	
		required.	
Government Oversight	State governments audited Waqf	Central government sets rules for	
	accounts; limited central role.	registration, audits; increased state	
		oversight via Collector.	
Financial Contribution	7% of income to Waqf Boards.	Reduced to 5%.	
Sectarian Boards	Shia Board if Shia Waqf exceeds 15% of	Adds Bohra and Aghakhani Boards	
	total Waqf assets.	alongside Shia/Sunni.	

वक्फ अधिनियम, 1995 के साथ तुलना

वक्फ आधानयम्, १५५५ क साथ तुलना				
पहलू	वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 संशोधनों के	वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025		
	साथ)			
नाम	वक्फ अधिनियम, 1995	एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और		
		विकास (यूएमईईडी) अधिनियम, 1995		
	सभी सदस्य (पदेन सदस्यों को छोड़कर) मुस्लिम होने	इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल हैं; दो मुस्लिम		
वक्फ बोर्ड संरचना	चाहिए; कम से कम दो महिलाएँ अनिवार्य। मुस्लिम	महिलाओं का होना अनिवार्य है; सभी सदस्यों को राज्य		
	सांसदों, विधायकों और बार काउंसिल के सदस्यों का	नामित करता है, चुनाव नहीं होते।		
	चुनाव।			
सीईओ की आवश्यकता	मुस्लिम अधिकारी (उप सचिव रैंक या समकक्ष) होना	सीईओ के लिए कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है।		
	चाहिए।			
सर्वेक्षण प्राधिकरण	राज्य द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त।	जिला कलेक्टर या उप-स्तर का अधिकारी।		
उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ	धार्मिक प्रयोजनों के लिए लंबे समय तक उपयोग की	भावी रूप से समाप्त; पूर्व-मौजूदा वक्फ-द्वारा-		
	जाने वाली संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता दी	उपयोगकर्ता संपत्तियां तब तक बनी रहेंगी जब तक कि		
	गई, यहां तक कि बिना किसी दस्तावेज के भी।	विवाद न हो।		
संपत्ति विवाद	वक्फ बोर्ड वक्फ की स्थिति निर्धारित कर सकता है	कलेक्टर जांच करेगा; न्यायाधिकरण के निर्णय के		
	(धारा 40); ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा जब तक	विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की		
	कि दुर्लभ मामलों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप न करे।	जा सकेगी।		
पारदर्शिता	कोई अनिवार्य केन्द्रीय पोर्टल नहीं; सीमित लेखापरीक्षा	पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत पोर्टल; उच्च आय वाले		
	प्रावधान।	वक्फों के लिए सीएजी ऑडिट।		







Link Life with Law

वक्फ निर्माण	कोई भी मुसलमान वक्फ बना सकता है; इसकी कोई	5+ वर्षों तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक;
	स्पष्ट अवधि नहीं है।	उत्तराधिकार अधिकार सुरक्षित।
न्यायाधिकरण संरचना	तीन सदस्य: न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,	तीन सदस्य: जिला न्यायाधीश, संयुक्त सचिव, मुस्लिम
	मुस्लिम कानून विशेषज्ञ।	कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं।
सरकारी निगरानी	राज्य सरकारों ने वक्फ खातों का ऑडिट किया; केंद्रीय	केंद्र सरकार ने पंजीकरण, लेखा परीक्षा के लिए नियम
	भूमिका सीमित कर दी गई।	निर्धारित किए हैं; कलेक्टर के माध्यम से राज्य की
		निगरानी बढ़ाई गई है।
वित्तीय योगदान	वक्फ बोर्ड को आय का 7%।	घटाकर 5% कर दिया गया।
सांप्रदायिक बोर्ड	यदि शिया वक्फ कुल वक्फ परिसंपत्तियों के 15% से	शिया/सुन्नी के साथ बोहरा और अगाखानी बोर्ड भी
	अधिक हो तो शिया बोर्ड।	जोड़े गए।

Governance and Autonomy:

- 1995 Act: Gave Waqf Boards significant autonomy, including the power to declare properties as Waqf (Section 40), often criticized for enabling unchecked claims and corruption (e.g., Karnataka Waqf Board land scam).
- 2025 Bill: Reduces Board autonomy by transferring key powers (surveys, disputes) to government officials like the District Collector, aiming to curb misuse but raising concerns about religious freedom (Article 26 of the Indian Constitution).

- 1995 अधिनियम: वक्फ बोर्डों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता दी गई, जिसमें संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की शक्ति भी शामिल थी (धारा 40), जिसकी अक्सर अनियंत्रित दावों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती थी (उदाहरण के लिए, कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि
- 2025 विधेयक: जिला कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारियों को प्रमुख शक्तियां (सर्वेक्षण, विवाद) हस्तांतरित करके बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है, जिसका उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26) के बारे में चिंताएं पैदा करना है।

2. **Inclusivity:**

- 1995 Act: Exclusively Muslim governance, reflecting Islamic law principles.
- 2025 Bill: Introduces non-Muslims and emphasizes women's representation, aligning with broader social inclusion goals but contested by some as diluting religious character.

समावेशिता:

- 1995 अधिनियम: विशेष रूप से मुस्लिम शासन, इस्लामी कानून सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है।
- 2025 विधेयक: गैर-मुस्लिमों को शामिल किया गया है और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है, जो व्यापक सामाजिक समावेशन लक्ष्यों के साथ संरेखित है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक चरित्र को कमजोर करने वाला बताया गया है।

3. **Transparency and Efficiency:**

- 1995 Act: Lacked modern tools like centralized databases; faced issues like poor revenue (₹163 crore annually vs. potential ₹12,000 crore, per the Sachar Committee).
- 2025 Bill: Leverages technology (central portal) and audits to improve management and revenue potential, benefiting societal welfare.

पारदर्शिता और दक्षता:

- 1995 अधिनियम: इसमें केंद्रीकृत डेटाबेस जैसे आधुनिक उपकरणों का अभाव था; कम राजस्व (सच्चर समिति के अनुसार, वार्षिक ₹163 करोड़ बनाम संभावित ₹12,000 करोड) जैसी समस्याओं का सामना करना पडा।
- 2025 विधेयक: प्रबंधन और राजस्व क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी (केंद्रीय पोर्टल) और लेखापरीक्षा का लाभ उठाएगा, जिससे सामाजिक कल्याण को लाभ होगा।

Dispute Resolution: 4.

- 1995 Act: Waqf Tribunals had near-final authority, often called "kangaroo courts" by critics due to limited appeals.
- 2025 Bill: Enhances judicial oversight with High Court appeals, applying standard legal timelines (Limitation Act), balancing Waqf rights with fairness.

Page-5







विवाद समाधान:

- 1995 अधिनियम: वक्फ न्यायाधिकरणों के पास लगभग अंतिम अधिकार थे, जिन्हें सीमित अपीलों के कारण आलोचकों द्वारा अक्सर "कंगारू अदालतें" कहा जाता था।
- 2025 विधेयक: उच्च न्यायालय की अपीलों के साथ न्यायिक निगरानी को बढ़ाता है, मानक कानूनी समयसीमा (सीमा अधिनियम) को लागू करता है, निष्पक्षता के साथ वक्फ अधिकारों को संतुलित करता है।

5. Property Claims:

- 1995 Act: "Waqf by user" and Board declarations led to controversial claims (e.g., Tamil Nadu village disputes).
- 2025 Bill: Eliminates "Waqf by user" prospectively and prioritizes government property rights, aiming to resolve encroachments but criticized for favoring state control.

संपत्ति दावे:

- 1995 अधिनियम: "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" और बोर्ड की घोषणाओं के कारण विवादास्पद दावे सामने आए (उदाहरण के लिए, तमिलनाडु गांव विवाद)।
- 2025 विधेयक: "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" को भावी रूप से समाप्त करता है और सरकारी संपत्ति अधिकारों को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य अतिक्रमणों को हल करना है, लेकिन राज्य नियंत्रण का पक्ष लेने के लिए इसकी आलोचना की जाती है।

Comparative table of **Section 2** of the original *Waqf Act, 1995* and its amended version under the *Waqf (Amendment) Act, 2025* (also referred to as the **UMEED Act**: Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act).

Comparative Analysis: Section 2 - Definitions

Sec.2	Waqf Act, 1995	Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act 1995 UMEED Act -1995 (Renamed)
Clause	Waqf Act, 1995 – Original Text	Waqf Amendment Act, 2025 – Amended Text
2(c)	"Waqf" means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable.	Expanded to include digital assets and income-generating ventures (e.g., solar farms, educational tech platforms) if dedicated for pious or charitable purposes. Also clarifies that "Waqf by user" is no longer recognized unless registered before enactment.
2(d)	"Waqf property" includes all property belonging to or given to a waqf.	Now requires mandatory registration on a centralized digital portal. Government land previously claimed as Waqf is excluded unless validated by Tribunal.
2(e)	"Mutawalli" means the person appointed to manage or administer a waqf.	Adds eligibility criteria: must disclose assets, undergo training, and be subject to annual audit. Also allows appointment of professional managers for large Waqfs.
2(g)	"Survey Commissioner" means the officer appointed under section 4.	Replaced by "District Collector or designated officer" for property surveys, aligning Waqf records with state revenue databases.
2(h)	"Tribunal" means the Waqf Tribunal established under section 83.	Tribunal now empowered to override Waqf Board decisions, fast-track disputes, and validate or reject historical Waqf-by-user claims.







New	_	Introduces "Waqf Development Entity" – a body to
Clause		promote sustainable use of Waqf assets (e.g., leasing for
		hospitals, schools, etc.) under strict guidelines.

	T	T
Section	Waqf Act, 1995 – Original Provision	Waqf Amendment Act, 2025 – Revised
		Provision
Section 3	- State Government to establish a Waqf Board	- Renamed as "Unified Wagf Board".
	·	•
Establishment of		- Mandatory inclusion of 2 Muslim women and 2
Boards	- Composition: Chairperson + Muslim members	non-Muslim members for transparency and
	(including scholars, elected representatives,	inclusivity.
	mutawallis).	- CEO need not be Muslim ; open to qualified
	- CEO must be Muslim.	professionals from any background.
		- Term limits and performance reviews
		introduced.
Section 4	- Survey Commissioner appointed by State	- Survey Commissioner replaced by District
Survey of Waqf	Government.	Collector or designated revenue officer.
Properties Properties	- Responsible for identifying and listing Waqf	- Survey integrated with state revenue records
rroperties	properties.	and GIS mapping.
	- Reports submitted to State Government and	- "Waqf-by-user" claims abolished unless
	Wagf Board.	registered before enactment.
	waqi boaid.	registered before effactifierit.
		- Survey results auto-synced to centralized digital
		portal.
Section 32	- Mutawalli responsible for administration,	- Mutawalli must undergo mandatory training
Powers and Duties	income utilization, and property protection.	and certification.
of Mutawalli	- Must maintain accounts and submit annual	- Required to disclose personal assets and avoid
	reports.	conflict of interest.
	- Removal possible for misconduct or	- Annual audit by CAG or designated officer if
	negligence.	income exceeds ₹1 lakh.
		- Large Waqfs may appoint professional
		managers under Board supervision.
		- Penalties for mismanagement increased;
		includes imprisonment and fines.

मूल वक्फ अधिनियम, 1995 की **धारा 2 और** वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (**जिसे उम्मीद अधिनियम** : एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम भी कहा जाता है) के तहत इसके संशोधित संस्करण की तुलनात्मक तालिका ।

🔲 तुलनात्मक विश्लेषण: खंड 2 - परिभाषाएँ

धारा 2	वक्फ अधिनियम, 1995	एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995
		उम्मीद अधिनियम -1995 (पुनर्नामांकित)
धारा	वक्फ अधिनियम, 1995 – मूल पाठ	वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 – संशोधित पाठ
2(सी)	"वक्फ" का अर्थ है किसी इस्लाम धर्मावलंबी व्यक्ति द्वारा किसी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या	डिजिटल संपत्तियों और आय-उत्पादक उपक्रमों (जैसे, सौर फार्म, शैक्षिक तकनीकी प्लेटफॉर्म) को भी इसमें शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है, बशर्ते वे धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हों। यह भी स्पष्ट





Link Life with Law

	धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना।	किया गया है कि "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" अब तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अधिनियमन से पहले पंजीकरण न कराया गया हो।
2(뢰)	"वक्फ संपत्ति" में वक्फ से संबंधित या उसे दी गई सभी संपत्तियां शामिल हैं।	अब एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पहले वक्फ के रूप में दावा की गई सरकारी भूमि को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा मान्य न कर दिया जाए।
2(ई)	"मुतवल्ली" का अर्थ है वह व्यक्ति जो वक्फ का प्रबंधन या प्रशासन करने के लिए नियुक्त किया गया हो।	पात्रता मानदंड जोड़े गए: संपत्ति का खुलासा करना होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और वार्षिक ऑडिट कराना होगा। बड़े वक्फों के लिए पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति की भी अनुमति दी गई है।
2(जी)	सर्वेक्षण आयुक्त से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी से है।	संपत्ति सर्वेक्षण के लिए "जिला कलेक्टर या नामित अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित, वक्फ रिकॉर्ड को राज्य राजस्व डेटाबेस के साथ संरेखित करना।
2(एच)	"न्यायाधिकरण" से तात्पर्य धारा 83 के अंतर्गत स्थापित वक्फ न्यायाधिकरण से है।	न्यायाधिकरण को अब वक्फ बोर्ड के निर्णयों को रद्द करने, विवादों को तेजी से निपटाने तथा ऐतिहासिक वक्फ-द्वारा-उपयोगकर्ता दावों को मान्य या अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है।
नया खंड		"वक्फ विकास इकाई" की शुरुआत की गई - यह एक निकाय है जो सख्त दिशानिर्देशों के तहत वक्फ परिसंपत्तियों (जैसे, अस्पतालों, स्कूलों आदि के लिए पट्टे पर देना) के सतत उपयोग को बढ़ावा देगा।

अनुभाग	वक्फ अधिनियम, 1995 – मूल प्रावधान	वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 – संशोधित प्रावधान
धारा 3	- राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के लिए एक वक्फ	- इसका नाम बदलकर "एकीकृत वक्फ बोर्ड" कर दिया गया है।
बोर्डों की	बोर्ड की स्थापना करेगी।	- पारदर्शिता और समावेशिता के लिए 2 मुस्लिम महिलाओं और 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को
स्थापना	- संरचना: अध्यक्ष + मुस्लिम सदस्य (विद्वान,	अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। - सीईओ का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है ;
	निर्वाचित प्रतिनिधि, मुतवल्ली सहित)। - सीईओ	किसी भी पृष्ठभूमि के योग्य पेशेवरों के लिए खुला है।
	मुस्लिम होना चाहिए।	
	3 (- कार्यकाल सीमा और प्रदर्शन समीक्षा शुरू की गई है।
	——————————————————————————————————————	-
धारा 4	- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त।	- सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर या नामित राजस्व अधिकारी को नियुक्त
वक्फ संपत्तियों	- वक्फ संपत्तियों की पहचान और सूची बनाने के	किया जाएगा। - सर्वेक्षण को राज्य के राजस्व रिकॉर्ड और जीआईएस मैपिंग के साथ एकीकृत
का सर्वेक्षण	लिए जिम्मेदार। - राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड	किया जाएगा। - "वक्फ-बाय-यूजर" दावों को समाप्त कर दिया जाएगा, जब तक कि
	को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	अधिनियमन से पहले पंजीकृत न किया गया हो ।
		- सर्वेक्षण परिणाम स्वचालित रूप से केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर सिंक हो जाएंगे।
धारा 32	- मुतवल्ली प्रशासन, आय उपयोग और संपत्ति	- मुतवल्ली को अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त करना होगा ।
मुतवल्ली की	संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।	- व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा करना और हितों के टकराव से बचना आवश्यक है। - यदि आय
शक्तियां और	- खातों का रखरखाव करना होगा और वार्षिक	
कर्तव्य	रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। - कदाचार या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	लापरवाही के लिए हटाया जा सकता है।	पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकते हैं । - कुप्रबंधन के लिए दंड में वृद्धि की गई है; इसमें
		कारावास और जुर्माना शामिल है।
		3

Page-8



Waqf Amendment Act, 2025 -

Click Here

Waqf Act, 1995 -

Click Here

Waqf Amendment Act, 2025 Judgment - Click Here

Linking Bare Act Linking Bare Act

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Unique Features

- 1. Sections Switching Table
- 2. Subject wise Division
- 3. Cut-Off (Result) Analysis
- 4. Chapter Wise Bifurcation
- 5. State Wise PYQ Coverage
- 6. Subject Weightage Analysis
- 7. Linked Provision & Explanation
- 8. Diglot Edition

Paperathon Booklet is smart analysis of in previous papers of judiciary exam







all questions covered



E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

Covered States

Available Bare Acts

- + Criminal Major Laws 2023 (BNS, BNSS, BSA)
- * Constitution of India
- **Criminal Minor Laws**
- **Civil Minor Laws**

CPC, 1908

Linking Support

Local Laws

988 774 6465 (Classes) 773 774 6465 (Publication)

Diglot

Edition

+ Family Laws

+ IT Act, 2000

* A&C Act, 1996

Environmental Laws

Advocate Act, 1961

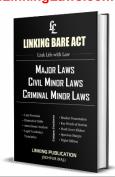
Land Acquisition, 2013

+ AIBE Additional Bare Acts

Consumer Protection Act, 2019



QR for Buy or visit w.LinkingLaws.com



E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

ALL-IN-ONE PAPERATHON°

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams. Available in English and Hindi Edition





English Edition



Hindi Edition

Scan this QR Order Now or visit www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at Linking App.

inking Charts $^{ extsf{@}}$



Major Laws Bird View



Linking Charts



Minor Laws & Alpha **Linking Charts**

Linking Bare Act

Available Bare Acts

1. Linking Criminal Manual 2. Constitution of India

5. BNSS 2023

3. Criminal Minor Laws 4. Civil Minor Laws

6. BNS 2023 7. BSA 2023 8. CPC 1908



Scan this QR Order Now or visit

www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**



©:773 774 6465 www.LinkingLaws.com

